27052015-ls-ngp-04.qxd 05/27/2015 12:12 PM Page 1

और.....एक शेर
आ गई है सहर अपना घर संभालने को
चलूं कि रात भर का जागा हुआ मैं भी हूं
-इरफान सिद्दीकी

लोकमत समाचार
नागपुर, बुधवार, 27 मई 2015

लोकमत समाचार
तमसो मा ज्योतिर्गमय

उस काम का चयन कीजिए जिसे आप पसंद करते हैं, फिर आपको पूरी जिंदगी एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा.
■ कन्फ्यूशियस

संपादकीय

निराधार आरोपों की पटरी पर राजनीति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कथन से अब यह तथ्य आईने की तरह साफ हो जाना चाहिए कि बोफोर्स तोप सौदे में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनकी सरकार और कांग्रेस को बेवजह कठघरे में खड़ा किया गया. इस मामले पर तुच्छ राजनीति हुई तथा बिना किसी सबूत के सिर्फ स्वीडन के मीडिया की खबरों के आधार पर तिल का ताड़ बना दिया गया. बोफोर्स तोप सौदे में तथ्यों की जांच किए बिना राजनीतिक दलों ने जिस तरह से कीचड़ उछाला, उससे सिर्फ एक पार्टी, एक सरकार या एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ही आघात नहीं पहुंचा बल्कि उससे देश के सम्मान को भी आघात पहुंचा. इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि हमारे राजनीतिक दल और उनके नेता सिर्फ अपने राजनीतिक हित के लिए काम करते हैं. वे उस हर चीज को अपना हथियार बनाने से नहीं चूकते जिससे उनका राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी घेरे में आता हो. आरोपों की तह में जाकर सबूत जुटाना वे अपना काम नहीं समझते. वे आरोपों की झड़ी लगाने के पहले यह तक नहीं सोचते कि मामला क्या है और उससे देश का हित और सम्मान कितना जुड़ा हुआ है. राष्ट्रपति का बोफोर्स तोप सौदे पर ताजा कथन देश की राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन व स्वार्थ की घृणित राजनीति को उजागर करता है. स्वीडन के एक अखबार को दिए गए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में कहा कि अब तक यह सिद्ध नहीं हो सका है कि बोफोर्स तोप सौदा एक घोटाला था. किसी भी भारतीय अदालत ने इस सौदे को घोटाला करार नहीं दिया है. मीडिया ने सारे मामले को उछाला. प्रणब मुखर्जी की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भाजपा भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर लगातार बरस रही है. कांग्रेस पर आरोप लगाते समय भाजपा करीब 25 सालों से बोफोर्स तोप सौदे में कथित दलाली का मामला उछालती है. यही नहीं उसने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजीव गांधी पर व्यक्तिगत आरोप लगाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी. बोफोर्स तोप का सौदा 1500 करोड़ रु. का था. स्वीडन की कंपनी से इसके लिए करार हुआ था. इस दौरान जब स्वीडन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओलोफ पाल्मे की हत्या हुई, तब उसे भी बोफोर्स तोप सौदे से जोड़कर देखा गया. बाद में साबित हुआ कि पाल्मे की हत्या दूसरे राजनीतिक कारणों से की गई थी. प्रणब के कथन पर भाजपा खामोश है. मंगलवार को मोदी सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा देते वक्त भाजपा अध्यक्ष अमित शाह राष्ट्रपति के ताजा कथन पर प्रतिक्रिया देने से कतरा गए. भाजपा के अन्य नेताओं के मुंह पर भी ताला लग गया. बोफोर्स तोप सौदे में बिना सबूत के आरोपों ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी. इसी मुद्दे को हथियार बनाकर विश्वनाथ प्रताप सिंह सत्ता में आए और इसके साथ ही राजनीतिक अस्थिरता का जो दौर शुरू हुआ, वह 1999 तक जारी रहा. 1989 से शुरू हुआ राजनीतिक अस्थिरता का दौर देश के लिए दुःखदायी साबित हुआ. देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई. वी.पी. सिंह ने जाति और भाजपा ने धर्म आधारित राजनीति शुरू की जिसने एकजुट भारतीय समाज में दरार पैदा कर दी. राष्ट्रपति के कथन पर बयान आएंगे, सफाई दी जाएगी और नए सिरे से आरोप-प्रत्यारोप लगेंगे. लेकिन राजनीतिक दलों को आत्ममंथन भी करना चाहिए कि देश बड़ा है या तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ. ■■

भय

''यह आनंद हैं. इनकी सबसे बड़ी खूबी है आदमी के भीतर का सच जान लेना. तुमसे पहली बार मिल रहे हैं, पर थोड़ी ही देर में तुम्हारे भीतर की एक-एक परत खोलकर रख देंगे.'' गली के मोड़ पर मिले मित्र ने उनसे मेरा परिचय करवाते हुए कहा.

लघुकथा

महेश दर्पण

''आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर आनंद.'' मैंने औपचारिकता निभाई.

''आइए, कुछ देर गप-शप हो जाए,'' कहा तो उसने बेहद सहज अंदाज में था, पर मैं घबरा गया. कहीं यह आदमी मुझे पढ़ लेना तो नहीं चाहता?

''देखिए, बात दरअसल यह है कि मैं बच्चे की दवाई लेने जा रहा हूं. आप लोग बैठिए, मौका लगा तो मैं जरूर आऊंगा.'' कहते हुए मैंने बचने का रास्ता निकाल ही लिया.

गली पार करते-करते मैं पसीना-पसीना हो आया था, यह सोचते हुए कि ऐसे लोग खतरनाक होते हैं. मैं उनके साथ बैठ जाता तो...? ■■

राजनीतिक रंग से बहता पानी

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

पानी पर हर तरफ हाहाकार! गर्मियों में इंसान और जानवर की प्यास बुझाने का संकट. बरसात में बाढ़ से बचाने की चुनौती. पानी के प्रबंध पर राजनीति के दांव-पेंच, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप. गंगा यमुना-नर्मदा-क्षिप्रा-कावेरी से समुद्र तक की आराधना -दीपों की आरती, पुष्प समर्पण- पाप धुलने और पुण्य पाने के संकल्प. लेकिन आपने कभी पता लगाने की कोशिश की है कि पिछले 45 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार में जल संसाधन मंत्रालय मिलने पर क्या कोई मंत्री और उसके सहयोगी प्रसन्न हुए हैं?

मेरा पत्रकारीय अनुभव इस मामले में दिलचस्प है. पिछली सरकारों में किसी जल संसाधन मंत्री से भेंट करने के लिए जाने पर उनके निजी सहायक ही नहीं मंत्री भी दुःखी मन से उत्सुकता दिखाते रहे कि मंत्रिमंडल में परिवर्तन की क्या संभावनाएं हैं और उन्हें कोई अच्छा 'वजनदार' मंत्रालय मिलने के क्या आसार हो सकते हैं? मतलब, जल संसाधन मंत्रियों को लगता है कि उन्हें अनावश्यक सा मंत्रालय सौंपा गया. यही कारण है कि पिछले दशकों में भारत के विपुल जल स्त्रोतों और भंडार का समुचित प्रबंध, योजना क्रियान्वयन और वितरण नहीं हो सका. प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में सीन नदी के सुंदर तटों पर दौरे के 'सेल्फी फोटो' जारी कर दिए, लेकिन गंगा, नर्मदा, क्षिप्रा के तटों को पर्यटन की दृष्टि से सुंदर बनाने की कोशिश नहीं की.

इंदिरा गांधी के सत्ताकाल में सिंचाई मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन की योजनाएं बनती थीं. के.एल.राव दूरदर्शी और पेशे से इंजीनियर होने के नाते

> दुनिया के किसी मुल्क में पानी के लिए ऐसी राजनीति देखने को नहीं मिलती. पड़ोसी चीन के साथ बराबरी के लिए बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन उससे जल प्रबंधन के उपयोगी फार्मूले सीखने की इच्छा नहीं दिखाई जाती.

काबिल सिंचाई मंत्री थे. उसके बाद कोई ऐसा इंजीनियर मंत्री इस मंत्रालय में नहीं आया और देर-सबेर इसका नाम ही जल संसाधन मंत्रालय हो गया. ऐसे मंत्रालयों में इंजीनियरिंग या तकनीकी शिक्षा प्राप्त सचिवों की नियुक्ति का विवाद भी उस समय गर्माया. 'टेक्नोक्रेट बनाम ब्यूरोक्रेट.' स्वाभाविक था कि ब्रिटिश राज से सत्ता के शतरंज में माहिर आईएएस लॉबी अधिक सफल रही. जब आईएएस कला-संगीत के संस्कृति मंत्रालय अथवा विमान सेवाओं का नागरिक उड्डयन मंत्रालय अथवा प्रसारण या मीडिया से जुड़े दूरदर्शन इत्यादि की बागडोर संभाल सकता है, तो बहते पानी पर सत्ता की नाव दौड़ाने में वह कैसे पीछे रह सकता है? इसी तर्क के आधार पर भारत के बाबुओं और अधिकांश नाकारा मंत्रियों ने जल संसाधनों के लिए सही कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं किया. हां, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों में लंबे-चौड़े भाषण अवश्य दिए.

जल संसाधनों पर काम करने वाले राजस्थान के राजेंद्र सिंह, गांधीवादी अनुपम मिश्र या गोपालकृष्ण अथवा बांध निर्माण के साथ गरीब लोगों के पुनर्वास की लड़ाई लड़ने वाली मेधा पाटकर और उत्तराखंड के चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा के अनुयायियों की सही बातें भी सरकारें नहीं सुनना चाहतीं. पानी से जुड़े आंदोलनों पर राजनीतिक रंग चढ़ा दिया जाता है. नर्मदा या बाणसागर पर बांधों के निर्माण पर दशकों तक राजनीतिक खींचातानी चलती रही. कावेरी पर दक्षिण भारत में घमासान होता रहा है. सबसे मजेदार स्थिति राजधानी दिल्ली की है, जहां हर साल हरियाणा की सरकार पानी रोकने की धमकियां देती है. समान पार्टियों की राज्य तथा केंद्र सरकारें होने पर भी सौदेबाजी होती है. दुनिया के किसी मुल्क में पानी के लिए ऐसी राजनीति देखने को नहीं मिलती. पड़ोसी चीन के साथ बराबरी के लिए बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन चीन से जल प्रबंधन के उपयोगी फार्मूले सीखने की कोई इच्छा नहीं दिखाई जाती. बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम जैसे राज्यों में हर साल भीषण बाढ़ से तबाही होती है. लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने अब तक ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए दूरगामी उपाय नहीं किए. नदी जल प्रबंध के साथ जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकारें और स्थानीय नगर निगम, पालिका, पंचायतें तालाब, बावड़ी को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयास करें. महानगरों और अन्य शहरों में वर्षा के दौरान जल संग्रहण के लिए सरकारी-गैर सरकारी संस्थाएं व्यापक अभियान चलाएं. सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए 20 हजार करोड़ रुपयों की योजनाएं बन सकती हैं, तो जीवन के लिए अनिवार्य जल भंडारण और वितरण के लिए 50 हजार करोड़ रुपयों का प्रावधान क्यों नहीं किया जा सकता है? बोतलबंद पानी और अन्य शीतल पेय बनाने वाली बहुराष्ट्रीय अथवा देशी कंपनियों से जल संसाधनों की रक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त शुल्क सरकारें वसूल सकती हैं. कस्बों और गांवों में अब जल सामान्य के लिए 'प्याऊ' लगाने की परंपरा भी खत्म सी हो रही है. राजनीति और सत्ता प्रतिष्ठानों से हटकर सामाजिक संस्थाएं जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. ■■

धर्मनिरपेक्षता के लिए नेहरू का संघर्ष

कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे संभवतः अकेले ऐसे महानायक हैं, जिनके विचारों में कतई कोई द्वैध यानी झोल नहीं दिखता. स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वे जिन मूल्यों के साथ रहे और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जैसे आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी भारत का निर्माण करना चाहा, उससे जुड़े उनके विचारों की यह कहकर तो आलोचना संभव है कि कई मामलों में वे कम्युनिस्टों के साथ खड़े दिखते हैं, हालांकि कई लोग इसकी उल्टी बात भी कहते हैं, लेकिन यह कहकर नहीं कि उनकी प्रगतिशीलता में कहीं कोई लोचा है.

आज जिस धर्मनिरपेक्षता को कई लोग संविधान की प्रस्तावना तक में बर्दाश्त नहीं करना चाहते, नव-स्वतंत्र देश में उसकी प्रतिष्ठा के लिए नेहरूजी ने हिंदू महासभा व संघ परिवार और कांग्रेस के भीतर के संकीर्णतावादी नेताओं के बीच के गठजोड़ से जमकर लोहा लिया था.

दरअसल, विभाजन के बाद हिंदू महासभा व संघ को पक्का विश्वास था कि वे देश की नई सांप्रदायिक स्थिति को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेंगे. गांधीजी की हत्या का दांव उल्टा पड़ा था, फिर भी कांग्रेस के अंदर के अपने शुभचिंतकों से उन्हें ढेरों उम्मीदें थीं. उनकी उम्मीदें फलवती होती भी दिखीं, जब अयोध्या में 22-23 दिसंबर, 1949 की रात बाबरी मस्जिद में जबरन मूर्तियां रख दिए जाने के मामले में यूपी के प्रीमियर गोविंदवल्लभ पंत ने नेहरू की अवज्ञा शुरू कर दी.

इसे लेकर नेहरू ने 17 अप्रैल, 1950 को पंत को लिखा, 'मैं पा रहा हूं कि सांप्रदायिकता आज उन लोगों के दिलो-दिमाग में भी प्रवेश कर चुकी है, जो इससे पहले कांग्रेस के स्तंभ हुआ करते थे. यह धीरे-धीरे बढ़ता हुआ लकवा है जिसे बीमार समझ भी नहीं पा रहा.' उन्होंने यह भी लिखा कि एक दिन वे अपनी पूरी शक्ति से इसके विरुद्ध अभियान शुरू करेंगे. दो मई, 1950 को उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा, 'हम संप्रदायों के बीच एकता का उद्देश्य भूल गए हैं. धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, पर उसे बहुत कम समझ पाए हैं.' फिर भी बात नहीं बनी तो 8 अगस्त, 1950 को सीधे पुरुषोत्तमदास टंडन को लिख दिया, 'आप भारत में लोगों की बड़ी संख्या के लिए सांप्रदायिक और पुरातनपंथी दृष्टि के प्रतीक बन गए हैं.' इसलिए कृपया कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव न लड़ें.

इसके बावजूद टंडन अगस्त, 1950 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े और जीते, तो श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने संतोष जताया और संघ का अंग्रेजी मुखपत्र 'आर्गनाइजर' इसको कांग्रेस के 'गांधी प्लस नेहरू' गुट की पराजय और 'गांधी प्लस पटेल' की जीत कहकर खुश हुआ.

फिर तो नेहरू की चुनौतियां खासी

पुण्यतिथि विशेष

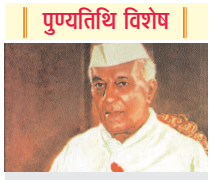

नव-स्वतंत्र देश में धर्मनिरपेक्षता की प्रतिष्ठा के लिए नेहरूजी ने हिंदू महासभा व संघ परिवार और कांग्रेस के भीतर के संकीर्णतावादी नेताओं के बीच के गठजोड़ से लोहा लिया था.

विकट हो गईं. लेकिन जल्दी ही उन्होंने बाजी पलट दी. सितंबर, 1950 में टंडन की बल्ले-बल्ले के बीच नासिक में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ तो नेहरू ने उसके मंच से आर या पार की शैली में कई कड़ी, खरी व दो-टूक बातें कहीं, 'पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं तो क्या हम भी यहां वही करें? ...आप मुझे प्रधानमंत्री के रूप में चाहते हैं तो आपको बिना शर्त मेरे पीछे चलना होगा. नहीं चाहते तो वैसा साफ-साफ कहें, मैं पद छोड़ दूंगा और कांग्रेस के आदर्शों के लिए स्वतंत्र रूप से लड़ूंगा.'

तीर निशाने पर लगा. उन्होंने सम्मेलन के प्रतिनिधियों का विश्वास तो जीता ही, भारत में धर्मनिरपेक्षता का भविष्य भी तय कर दिया. 'न्यूयॉर्क टाइम्स' ने अपने 22 सितंबर, 1950 के अंक में लिखा, 'अब तय हो गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनने की ओर बढ़ेगा, न कि परंपरावादी हिंदू गुट द्वारा शासन की ओर.'

इतिहास गवाह है, इसके बाद टंडन को पद छोड़ना पड़ा और 1952 में आम चुनाव हुए तो मतदाताओं ने भी नेहरू की धर्मनिरपेक्ष नीतियों पर मुहर लगा दी. ■■

न्याय की बदलती अवधारणा

संतोष देसाई
ग्ल्यूबरब्रांड्स ग्रुप के एमडी और सीईओ

हिट एंड रन मामले में सलमान खान के बारे में अदालती फैसले ने जिस तीव्रता से हमारा ध्यान आकर्षित किया, उसमें विशेष आश्चर्य की बात नहीं है. हाल के समय की कुछ सबसे बड़ी बहसें सजा के विचार के आसपास घूमती लगती हैं. इस मामले के अलावा, हम

> परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित न्याय का विचार बदल रहा है और यह संक्रमण का समय है.

वैवाहिक बलात्कार को पहचानने और उसे दंडित करने की भावनात्मक बहस के बीच में भी हैं. हमने बलात्कार के मामलों में मौत की सजा को लागू करने के बारे में ज्यादा उत्साह देखा है, साथ ही ऐसे जघन्य अपराधों के मामले में दोषी पाए गए किशोरों को भी दंडित करना संभव बनाना चाहते हैं.

इन बहसों में न्याय के विचार और उसके भीतर सजा की भूमिका को लेकर कई मानसिकताएं हैं. सलमान खान के बारे में बहस में उदाहरण के तौर पर हम इस मानसिकता को देखें. उनके अपराध की जानकारी होने पर भी हम उसे हल्का करने की कोशिश में तर्क देते हैं कि वे एक अच्छे आदमी हैं जिसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, लोगों को फुटपाथ पर नहीं सोचा चाहिए, फैसला आने में बहुत देर हो चुकी है, सलमान को सेलिब्रिटी होने के कारण निशाना बनाया गया है आदि-आदि. यहां बचाव प्राथमिक तथ्यों को शामिल करने वाली कानूनी प्रकृति का नहीं है, बल्कि अपराध को बड़े सामाजिक संदर्भ में ले जाने की कोशिश है और न्याय के बारे में व्यापक तरीके से सोचने की मांग है.

दूसरे पक्ष का दृष्टिकोण है कि न्याय की कल्पना एक परिपूर्ण विचार है और वह यह नहीं देखता कि संबंधित व्यक्ति कौन है. चाहे सलमान खान अच्छे आदमी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सिर्फ एक बात मायने रखती है कि मामले में संबंधित व्यक्ति को अगर दोषी साबित किया जा सकता है तो फिर कानून अपना काम करता है.

इसी पैटर्न का एक विवादास्पद सवाल वैवाहिक बलात्कार के अपराध का है. मुद्दे को सामाजिक दृष्टि से देखें तो विवाह के संदर्भ में इसे बलात्कार के रूप में पेश कर पाना कठिन है. दुनिया की नजर में शादी के संदर्भ में बलात्कार का विचार ही नियमों के बाहर है. समस्या शादी के भीतर हिंसा को अपराध मानने की ज्यादा नहीं, बल्कि यौन हिंसा को बलात्कार के रूप में वर्गीकृत करने में है. विवाह आधारित प्रणाली में सहमति की अवधारणा हमेशा से एक धुंधला क्षेत्र रही है. जबकि दूसरे पक्ष के समर्थकों का तर्क है कि किसी भी तरह के यौन संपर्क में, बिना किसी अपवाद के, महिला की सहमति होना आवश्यक है, अन्यथा वह बलात्कार है.

परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित न्याय का विचार बदल रहा है और यह संक्रमण का समय है. ■■

नजर के पार

आईएसआईएस के हमलों से अमेरिका बेफिक्र!

सारंग थते
सेवानिवृत्त कर्नल

इराक की राजधानी बगदाद से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है अल अनबार प्रदेश की राजधानी रमादी, जिस पर आईएसआईएस के लड़ाकों ने 17 मई को कब्जा कर लिया है. इराक के एक बड़े इलाके में आईएसआईएस ने अपनी पकड़ एक बार फिर मजबूत बना ली है.

पेंटागन की ताजा रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा मंत्री एश कार्टर ने इस बात को खुले रूप में माना है कि रमादी की लड़ाई में इराकी सेना ने अपने घुटने सिर्फ इसलिए टेक दिए क्योंकि सेना में आईएसआईएस से लड़ने का जज्बा ही नहीं था. इसे बेहद चौंकाने वाला वक्तव्य तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे पहले भी आईएसआईएस की भीषण लड़ाइयों में इराकी सेना के बनिस्बत कुर्द लड़ाकों ने ज्यादा शिद्दत से दुश्मन का मुकाबला किया था - क्योंकि इस जनजाति के लड़ाकों को जमीन की पहचान बेहतर थी और उसकी बदौलत उन्होंने आईएसआईएस को पहले भी शिकस्त दी थी. लेकिन इस बार इस प्रमुख शहर रमादी को बचाने का जिम्मा इराकी सेना के जिम्मे था जिसमें इराकी सेना को मुंह की खानी पड़ी है. कार्टर के मुताबिक आईएसआईएस के लड़ाकों के मुकाबले में इराकी सेना की संख्या रमादी में कहीं ज्यादा थी लेकिन कमी थी तो दुश्मन से लोहा लेने के जोश की और इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा है.

रमादी की जंग ने सभी को एक जबर्दस्त झटका दिया है. अमेरिका और इराक को इस समय एक और दोधारी

तलवार का रूप देखने को मिल रहा है. जहां एक तरफ जनजातीय लड़ाके 'आखिरी गोली-आखिरी दुश्मन' तक लड़ाई लड़ रहे हैं और आईएसआईएस को नाकों चने चबवा रहे हैं, वहीं उन्हें मिलने वाले हथियारों का जखीरा भी बढ़ता जा रहा है. मुख्यतः पशमर्गा लड़ाकों को मिले हुए हथियार ईरान से मिले हैं. कई अन्य मध्यपूर्व के देश इस इलाके में हथियार और गोलाबारूद भेज रहे हैं. आने वाले दिनों में इस प्रकार के हथियार कहीं इराक की नई सरकार की नींव को खोखला ना कर दें, इस पर भी चिंता बनी हुई है. वैसे भी अमेरिका यही कहता आया है कि यदि लंबे समय के लिए इराक में शांति के प्रयास करने हों तो इलाके में मौजूद सरकार को सभी गुटों से मिलकर उनकी रजामंदी से सरकार में शामिल करना होगा.

इस बढ़ते हुए संघर्ष में ओबामा प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं- इतने महीनों में हुए नरसंहार से निपटने के लिए सिर्फ हवाई हमले ही काफी नहीं हैं और गठबंधन की सेना को जमीन पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, इस जरूरत को नकारा नहीं जा सकता. अमेरिका में रक्षा विशेषज्ञ यह मानते हैं कि ओबामा सरकार की इराक में नौ साल की जंग के बाद ली जा रही राजनीतिक पहल न के बराबर हो गई है. विश्व के सबसे ताकतवर देश से सबको उम्मीदें हैं पर ओबामा सरकार ने अपने हाथ बांध लिए हैं. क्यों? यह प्रश्न इराक के बाशिंदे शायद हर मौत के बाद पूछते होंगे. ■■

तोल बोल

अगर कोई मेरे देश को नुकसान पहुंचाता है तो मुझे सक्रिय और सख्त कार्रवाई करनी होगी. सेना का उद्देश्य भी यही है कि हमलावर पर जवाबी कार्रवाई करे.
■ मनोहर पार्रिकर, रक्षा मंत्री

अनुच्छेद 370 रातों-रात छूमंतर होने वाला नहीं है. अलबत्ता इस पर अंतिम फैसला लेने से पहले जम्मू-कश्मीर की जनता को इसके नफे-नुकसान को समझना होगा.
■ मीनाक्षी लेखी, भाजपा नेता

gñWmnHi gmXHi :
ñd. Odñabrib XSñ
M`à_Z, E[SO(à`b ~ïS :
{dO` XSñ
E[SO(à-BZ-Mr\i :
anOÐ XSñ
gmXH :
{dHñrg {_I ★
★ nr. Aïa. ~r. HñZZ Hi
AZgïa gnU gmXHñ` Xo(` Ed
Hi {bE {Oå_Xïa.

© लोकमत समाचार _ àHñ{eV g^r gr_Jr Hñ gdr{YHïa brHi_V _r{S`ï àr`d\ {b. Hi mg ga{jV h.
brHi_V _r{S`ï àr`d\ {b. Hi {bE _ÐHi Ed àHñeHi बालाजी मुले Ûïar brHi_V _r{S`ï àr`d\ {b., ñbr{O Hi. 192, 207, 208 E_. Aïñ. Sr. gr. B\S(fñ` Б E[à`ï, ~0r~ïar, ZJna _ {ÐV Ed brHi_V ^dZ n. Odñabrib Zñèi _ïJ, ZJna _ àHñ{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XïUd{Z : 0712-2423527 (7 brB\g) \ïŠg : 6618555
Email : gmXHi` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkmZ : advt.ngp@lokmat.com {dVïU : circ.ngp@lokmat.com

इतिहास पर नजर 27 मई

आज ही के दिन वर्ष 1994 में रूसी मूल के उपन्यासकार अलेक्सांद्र सोल्जेनित्सिन की अमेरिका में 20 साल तक निर्वासन में रहने के बाद रूस में घर वापसी हुई थी. सत्ता विरोधी लेखन के कारण सोल्जेनित्सिन की नागरिकता 1974 में रद्द कर दी गई थी और उन्हें सोवियत संघ से बाहर निकाल दिया गया था. सोल्जेनित्सिन को सोवियत संघ में प्रचलित गुलाग प्रथा के बारे में उनके लेखन को लेकर ख्याति मिली थी. सोल्जेनित्सिन की नागरिकता को 1990 में सोवियत संघ के अंतिम सर्वोच्च नेता मिखाईल गोर्बाचेव ने बहाल किया. वर्ष 2008 में 89 वर्ष की उम्र में सोल्जेनित्सिन का निधन हो गया. ■■

- 1538-जिनेवा में धर्मसुधार आंदोलन के प्रणेता जॉन केल्विन और उनके शिष्यों को शहर से निकाला गया.
- 1805-नेपोलियन बोनापार्ट इटली का सम्राट बना.
- 1896-रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय सम्राट बना.
- 1940-अमेरिका में हेलिकॉप्टर की पहली सफल उड़ान भरी गई.
- 1951-बांबे (अब मुंबई) में तारापुरवाला एक्वेरियम का उद्घाटन.
- 1957-कॉपीराइट बिल पारित हुआ.
- 1973-बहरीन में संविधान को अंगीकार किया गया.

पाठकों के पत्र

परंपराओं का अपमान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से कि एक साल पहले तक लोग कहा करते थे- 'जाने कौन सा पाप किया था जो भारत में पैदा हुए' हिंदुस्तान की गौरवशाली परंपराओं का अपमान हुआ है.

जिस 5000 साल पुरानी भारतीय सभ्यता पर हम गर्व करते हैं, जिसके आधार पर भारत को विश्वगुरु बनाने का दावा करते हैं, उसे नमो ने एक झटके में खारिज कर दिया. संस्कृत, वेद, गीता, दशमलव, तुलसी, नीम, ऋषि मुनि-कणाद, आर्यभट्ट, चरक, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसी विभूतियां इसी भारत भूमि की उपज हैं.

ये क्यों भूला जाए कि राणा प्रताप, शिवाजी, सरदार पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, गोलवलकर गुरुजी आदि शख्सियतें इसी देश की पहचान हैं. इन मुद्दों पर बयान को परखने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा.
■ इंदिरा किसलय, नागपुर

सच या झूठ?

एक नाविक तीन साल से एक ही जहाज पर काम कर रहा था. एक दिन नाविक शराब में नशे में धुत हो गया. ऐसा पहली बार हुआ था. कैप्टन ने इस घटना को रजिस्टर में इस तरह दर्ज किया, ''नाविक आज रात नशे में धुत था.''

नाविक ने यह बात पढ़ ली. नाविक जानता था कि इस एक वाक्य से उसकी नौकरी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. इसलिए वह कैप्टन के पास गया, माफी मांगी और कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी लिखा है, उसमें ये जोड़ दे कि ऐसा तीन साल में पहली बार हुआ है, क्योंकि पूरी सच्चाई यही है.

विविध

किरण साहू

कैप्टन ने उसकी बात मानने से साफ इंकार कर दिया और कहा कि मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में दर्ज किया है. वही सच है.

कुछ दिनों बाद नाविक की रजिस्टर भरने की बारी आई. उसने रजिस्टर में लिखा- ''आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी है.''

कैप्टन ने इसे पढ़ा और नाविक से कहा कि इस वाक्य को आप या तो बदल दें अथवा पूरी बात लिखने के लिए आगे कुछ और लिखें, क्योंकि जो लिखा गया था, उससे जाहिर होता था कि कैप्टन हर रोज रात को शराब पीता था. नाविक ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा है, वही सच है.

दोनों बातें सही थीं, लेकिन दोनों से जो संदेश निकल रहा था, वह झूठ के समान था. ■■